STATEMENT RE. COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1973.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-4348/73.]

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I bring a serious matter to the notice of the Hon'ble House, under Rule 377.

Sir, as reported by the *Hindustan Times* dated the 28th February, 1973 a ruling party MLA of Gujarat informed the party legislators in their meeting that one family had died because of starvation in his constituency. That constituency is a part of my Parliamentary constituency also.

I draw the attention of the Government to these reported deaths, caused by starvation and appeal to them to increase the supply of foodgrains and other essential commodities and rush them immediately to hard hit areas of Gujarat..

MR. SPEAKER: We shall resume discussion on the Railway Budget after Lunch. Every day, because many things arise, we shift our time after 1 p.m. and so our meeting after lunch also gets delayed. Government time, according to our calculations, is reduced. We have today to take up Private Members' business at the fixed hour. The result is that every day whatever we have decided in the Business Advisory Committee gets upset. We have to bear this in mind.

13.40 hrs.

The Lok Sabha reassembled after till Forty-Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reasembled after at Forty-nine Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now resume the general discusison on the Railway Budget. Shri Ismail.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि उड़ीसा में कुछ एम० एल० एज० को पटनायक ने घर में बन्द कर रखा है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह उन की रक्षा की व्यवस्था करें।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : वहां के मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। अब वहां कोई सरकार नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाये, ताकि वह इस बात की जांच कर सके।

RAILWAY BUDGET, 1973-74—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ismail.

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर साल किराया और टैक्स बढ़ाने की जो पद्धति और तरीका चला आ रहा है, उस का इस साल के रेलवे बजट में भी अनुसरण किया गया है। इस बीच में जो जैनरल बजट रखा गया है, उस में भी इसी तरह टैक्स बढ़ाये गये हैं। यह सरकार सोशलिज्म और गरीबी हटाने के जिस लक्ष्य और आदर्श को सामने रख कर चलने का दावा करती है, रेलवे बजट और जैनरल बजट दोनों उस के विरोधी हैं।

जहां तक रेलवे बजट का सम्बन्ध है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस में गरीबों के लिए किराया कम बढ़ाया गया है,

[श्री महम्मद इस्माइल]

और फर्स्ट क्लास का किराया ज्यादा बढ़ाया गया है। मैं कहना चाहता हुं कि जो लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, उन में कम से कम 75 परसेंट तो रेलवे ग्राफिसर्ज और गवर्नमेंट ग्राफिसर्ज होते हैं। दूसरे लोग बहुत कम फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं। जो बड़े लोग हैं, वे ज्यादातर हवाई जहाज से जाते हैं। इस तरह जो किराया बढ़ाया गया है, उस का ग्रसर गरीबों पर ही पड़ेगा।

इस देश में कुछ समय से—ग्राजादी की सिल्वर जुबिली के बाद से—चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हर एक ग्रादमी जानता है, देश के लोग जानते हैं कि चावल से ले कर लकड़ी, तेल, कोयला और चीनी सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और उस का बोझ उन पर पड़ रहा है। लेकिन माल्म होता है कि सरकार यह बात नहीं जानती है। मौजूदा हालत में रेल का किराया और फ्रेट बढ़ाने का नतीजा क्या होगा? चीजों के दाम और बढ़ेंगे। सरकार कहती है कि वह दामों को बढ़ने से रोकेगी। लेकिन वह पच्चीस साल तक ऐसा नहीं कर सकती है। और न ग्रागे कर सकती है (व्यवधान) सरकार की तरफ से यह पालिसी डिक्लेयर की जाती है, कि हमारा लक्ष्य सोशलिज्म है।

देश में ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता जो यह फर्क है ग्रमीर और गरीब का इस को हम मिटाते जा रहे हैं। ग्रब इस बजट में क्या यह कहीं है? इस में तो गरीब के ऊपर 4 रुपया चीनी का दाम चढ़ा हुग्रा है और किराया बढ़ा कर उस के ऊपर वह और भार लाद दिया है। मिट्टी में वह पहले ही दबा है। सिर्फ सिर उस का ऊपर है। उस सिर को भी दबा दिया। यह जनता पर सीधा हमला है। इस बजट के ग्रन्दर जनता पर सीधा हमला है। ग्राप चाहे यह जितना भी कहें कि दाम नहीं बढ़ेंगे देश की जनता उस पर एतबार नहीं करती है। वह यह समझ गई है कि हर साल बजट सैशन ग्राएगा कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बजट से पहले देना पड़ेगा और बजट के बाद उस के ऊपर और बढ़ेगा। जैसे सरकार ने पहले ही कोयले का दाम बढ़ा दिया है 6-7 रुपये हो गया है और ग्रब यह टैक्स लगने के बाद साढ़े सात और ग्राठ होने वाला है। यह ग्रादत किस ने बनाई है? सोशलिज्म की बात जो लोग करते हैं उन्होंने यह ग्रादत पैदा की है। देश की जनता में यह धारणा ग्राप की पालिसी ने पैदा की है। मैं मिश्रा जी पर गुस्सा नहीं हूं, मुझे उन की सारी पालिसी पर गुस्सा है। ग्राप की पालिसी ने यह सर्वनाश किया है हमारे देश का और ग्राप की पालिसी की वजह से गरीब पर यह मुश्किलें ग्रा रही हैं। यह बजट उस का सबूत है। ग्राप सोशलिस्ट स्टेट बनाने की बात करते हैं। मगर वर्कर्स के बारे में इस बजट के ग्रन्दर मंत्री महोदय को एक भी लफ्ज नहीं है। बल्कि उलटे मजदूरों को गालियां दी गई हैं कि उन को पैसे देने पड़े, उन की तनख्वाह बढ़ी हैं, डीग्ररेनेस एलानेंस बढ़ाना पड़ा हैं इसलिए यह किराया बढ़ रहा है। और जो ग्राप का ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उस में जो चोर बैठे हुए हैं उन का जिक्र नहीं किया है। ग्रभी ग्राप की रेलवे कन्वेंशन कमेटी ने ग्रार पी एफ के बारे में क्या लिखा है? चोरियों की क्या हालत है? रेलवे की प्रापर्टी पब्लिक की प्रापर्टी की क्या हालत है? मैं फिगर कुछ देना चाहता हूं। वैसे मंत्री महोदय को तो यह मालूम ही होगा कि क्या हालत हो रही हैं, 1968-69 में 36 लाख रुपये की चोरी हुई थी और 71-72 में वह बढ़ कर के 1 करोड़ 73 लाख हो गई है। इधर किराया बढ़ा और उधर चोरियों की रकम 1 करोड़ 73 लाख हो गई। इस बारे में एक लब्ज नहीं कहा। मगर मजदूरों के बारे में यह है कि उन को देना पड़ा। यह जो लेकर भाग गए हैं और जो चोरियां हो गई हैं उन को मंत्री महोदय ने नहीं बताया। ग्रभी हाल में 72-73 का 6 महीने का हिसाब बताया गया है, उसे मैंने देखा है, कि इन 6 महीनों में 1 करोड़ 13 लाख की चोरी हो चुकी

और 6 महीने अभी और बाकी हैं । उस में और भी ज्यादा चोरियां होंगी । इस के बारे में कोई बात नहीं कहीं हैं और वर्कर्स के बारे में कहा कि इन को इतना देना पड़ा । यह रेलवे बजट जो है उस में जनता और वर्कर्स के अन्दर झगड़ा लगाने की बात कही गई है । कहां तो दोस्ती की बात कहनी चाहिए थी और कहां झगड़े की बात कही गई है । एक तो देना पड़ा है और पै कमीशन की रिपोर्ट निकलेगी तो और देना पड़ेगा । आप अपनी कमजोरियां और अपने दिवालियेपन को सेल्फ-क्रिटिकली नहीं देखते, उस की समालोचना नहीं करते ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may continue on Monday.

Now we take up Private Members' Business. There is a motion by Shri Parashar.

15.00 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-THIRD REPORT

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th February, 1973."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th February, 1973."

The motion was adopted

15.01 hrs.

RESOLUTION RE: LAND REFORMS IN THE COUNTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further discussion of the following Resolution moved by Shri A. K. Gopalan on the 8th December, 1972:

"This House calls upon the Central Government to recommend to all the State Governments to enact effective land reforms before the 26th January, 1973, through which the land monopoly of landlords is broken, all the exemptions are done away with and ceiling is fixed in such a way so that sufficient land is made available for distribution to the agricultural workers and poor peasants."

Before that, there is a formal amendment given notice of By Shri A. K. Gopalan. Would he like to move it?

SHRI A. K. GOPALAN (Palghat): I move:

That in the Resolution,—

for "26th January, 1973"

substitute "30th May, 1973" (6)

MR. DEPUTY-SPEAKER: On the last occasion, Mr. Bhogendra Jha was on his legs. Is he here?...No, he is not here. Shri E. R. Krishnan.

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Hon Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Resolution on Land Reforms moved by my hon. friend, Shri A. K. Gopalan.

---

*Original speech was delivered in Tamil.